दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

मई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड 3
- बंदर एवं लंगूर गणना, 2021 3
- मसूरी की राधा ने 1500 मीटर रेस में जीता गोल्ड मेडल 4
- उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच वर्षों पुराने विवाद का समाधान 4
- उत्तराखंड में चाइल्ड स्टंटिंग के मामलों में 7% की कमी 5
- रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम परिसर का भूमिपूजन 5
- कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन.के. जोशी को 'उत्तराखंड रत्न' सम्मान 5
- सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैरिफ जारी 6
- सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैरिफ जारी 6
- मनेरी डैम 7
- हेलंग-मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी 7
- उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति 7
- ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा के जलस्तर में एकाएक वृद्धि 8
- हिमालयन बर्ड सर्वे 8
- 'अपात्र को ना-पात्र को हाँ'अभियान 9
- शिव सर्किट में शामिल होगी 'महादेव गुफा' 9
- म्युनिसिपल (Muni) बांड जारी करने की दिशा में उत्तराखंड का प्रयास 10
- उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 31 नए हेलीपैड 10

नोट :

उत्तराखंड

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- नई शिक्षा नीति के तहत तैयार पाठ्यक्रम को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के चलते वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा।
- प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में चॉइस इस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के तहत छात्रों का क्रेडिट बैंक बनेगा, इसी के आधार पर उनका एक से दूसरे महाविद्यालयों में दाखिला हो सकेगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोज़गारपरक भी बनाया गया है।

बंदर एवं लंगूर गणना, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में अयोजित बंदर एवं लंगूर गणना के आँकड़े जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस गणना का आयोजन उत्तराखंड वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया है।
- इसके अनुसार प्रदेश में बंदरों की संख्या में 2015 की तुलना में वर्ष 2021 में 24.55 फीसदी की कमी आई है, जबकि लंगूरों की संख्या में 31.14 फीसदी की कमी आई है।
- वर्ष 2021 में हुई गणना में बंदरों की संख्या 1,10,481 और लंगूरों की संख्या 37,735 दर्ज की गई, जबकि साल 2015 में बंदरों की संख्या 1,46,432 तथा लंगूरों की संख्या 54,804 थी।
- गणना के अनुसार बंदरों की संख्या का वितरण इस प्रकार है- हरिद्वार वन प्रभाग > बागेश्वर वन प्रभाग > देहरादून वन प्रभाग।
- गणना के अनुसार लंगूरों की संख्या का वितरण इस प्रकार है- कॉर्बेट रामनगर > बद्रीनाथ वन प्रभाग > कॉर्बेट कालागढ़।
- बंदरों की संख्या कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं-
- बंदरों की नसबंदी का कार्यक्रम

नोट :

- बंदर बाड़ों का निर्माण
- रेस्क्यू सेंटरों का निर्माण, जैसे- मिनी ज़ू रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा।
- प्रदेश में दो बंदर वन बनाए जाएंगे; पहला हल्द्वानी में 107 हेक्टेयर में, जबकि दूसरा हरिद्वार में 25 हेक्टेयर में।

मसूरी की राधा ने 1500 मीटर रेस में जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2022 को बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 में उत्तराखंड के मसूरी की 23 वर्षीय राधा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता।

प्रमुख बिंदु

- राधा ने यह दौड़ 4 मिनट 31 सेकंड में पूरी की और शानदार प्रदर्शन के दम पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं।
- 23 वर्षीय राधा सिंह महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एक्सीलेंसी विंग की खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी राधा राष्ट्रीय स्तर पर दो मेडल जीत चुकी हैं।
- राधा सिंह के प्रशिक्षक अनूप बिष्ट ने बताया कि 1500 मीटर दौड़ में राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि हिमाचल की सुनीता ने द्वितीय और मणिपुर की हुईदरोम देवी ने तीसरा स्थान हासिल किया।
- उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु में 24 अप्रैल से 3 मई, 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 का आयोजन किया गया।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत युवा छात्रों को विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिये प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 31 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच वर्षों पुराने विवाद का समाधान

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त प्रेसवार्त्ता करके बताया कि दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का 21 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- समाधान के तहत अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को दे दिया गया है और भागीरथी होटल यूपी सरकार को मिल चुका है।
- गौरतलब है कि भागीरथी पर्यटक आवास गृह का निर्माण अलकनंदा होटल के बदले उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई ज़मीन पर किया गया है।
- हरिद्वार में 43.26 करोड़ रुपए की लागत से 2964 वर्ग मीटर में बने इस भागीरथी पर्यटक आवास गृह में 100 कमरे हैं।
- उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों के बीच बहुत-सी विवादास्पद संपत्तियों में से ही एक होटल अलकनंदा भी था। इसके समाधान के लिये उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आधिकारिक स्तर की वार्त्ता शुरू की गई थी।

नोट :

उत्तराखंड में चाइल्ड स्टंटिंग के मामलों में 7% की कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पाँचवे दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में स्टंटिंग में 7% की उल्लेखनीय कमी दर्ज़ की गई है।

प्रमुख बिंदु

- पिछले चार वर्षों में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38 से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है।
- 2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) में बच्चों में अधिक स्टंटिंग पाई गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में स्टंटिंग पुडुच्चेरी में सबसे कम (20%) और मेघालय में सबसे ज्यादा (47%) पाई गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में स्टंटिंग में 7% की कमी जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश और मणिपुर में 6 प्रतिशत तथा चंडीगढ़ और बिहार में 5 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गई है।

रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम परिसर का भूमिपूजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के 162वें जन्मोत्सव वर्ष समारोह में शिरकत कर विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम परिसर के लिये भूमिपूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस विश्वविद्यालय का निर्माण नैनीताल ज़िले के रामगढ़ में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ पहाड़ी पर ही टैगोर हिल बसा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ वर्षों पहले आकर गुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने साहित्य लिखकर विश्व के नक्शे में रामगढ़ का नाम अमिट कर दिया था।
- इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने 45 एकड़ भूमि 'शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय' नामक ट्रस्ट को दान की थी।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन.के. जोशी को 'उत्तराखंड रत्न' सम्मान

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2022 को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटलेक्चुअल संस्था की ओर से नैनीताल में मनाई गई 44वीं वर्षगाँठ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये प्रो. एन.के. जोशी को 'उत्तराखंड रत्न' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रो. जोशी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य, विश्वविद्यालय में लागू नवाचार, अभिनव, नवप्रवर्तन कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन एवं उत्कृष्टता के साथ की गई अकादमिक सेवाओं को रेखांकित करते हुए यह सम्मान प्रदान किया गया है।
- प्रो. जोशी के प्रयासों से कुमाऊँ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के शीर्ष केंद्र के रूप में जगह बना रहा है।
- प्रो. जोशी के प्रयासों के चलते उच्च शिक्षा संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कुमाऊँ विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में 58वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं QD एशिया रैंकिंग में विश्वविद्यालय को 551-600 स्थान मिला है।

नोट :

सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैरिफ जारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (उरेड़ा) के नए प्रोजेक्ट को पुरानी दरों पर स्थापित करने की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए दो साल के बाद सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिये नया टैरिफ जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- उरेड़ा के पास मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के तहत 1472 आवेदन आये थे, जिनमें से 781 प्रोजेक्ट को उरेड़ा ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था। कोविड महामारी और फिर विधानसभा चुनाव की वज़ह से इन प्रोजेक्ट की स्थापना धीमी हो गई थी।
- नियम यह था कि जो भी प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2022 तक स्थापित होंगे, केवल वही 4.49 रुपए प्रति यूनिट की दर से यूपीसीएल को बिजली बेच सकेंगे।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व ज़िला सहकारी बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकेंगे तथा शेष राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत ज़िलों में यह अनुदान 30 प्रतिशत तक होगा और पर्वतीय ज़िलों में 25 प्रतिशत तक और अन्य ज़िलों में 15 प्रतिशत तक ही होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे।
- इसके तहत राज्य के 10 हज़ार बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।

सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैरिफ जारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (उरेड़ा) के नए प्रोजेक्ट को पुरानी दरों पर स्थापित करने की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए दो साल के बाद सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिये नया टैरिफ जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- उरेड़ा के पास मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के तहत 1472 आवेदन आये थे, जिनमें से 781 प्रोजेक्ट को उरेड़ा ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था। कोविड महामारी और फिर विधानसभा चुनाव की वज़ह से इन प्रोजेक्ट की स्थापना धीमी हो गई थी।
- नियम यह था कि जो भी प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2022 तक स्थापित होंगे, केवल वही 4.49 रुपए प्रति यूनिट की दर से यूपीसीएल को बिजली बेच सकेंगे।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व ज़िला सहकारी बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकेंगे तथा शेष राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत ज़िलों में यह अनुदान 30 प्रतिशत तक होगा और पर्वतीय ज़िलों में 25 प्रतिशत तक और अन्य ज़िलों में 15 प्रतिशत तक ही होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे।
- इसके तहत राज्य के 10 हज़ार बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :

मनेरी डैम

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग बह जाने से मनेरी डैम के पास एक टापू पर 7 मज़दूर फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मनेरी बाँध उत्तरकाशी ज़िले में भागीरथी नदी पर स्थित एक कंक्रीट ग्रेविटी बाँध है। बाँध का प्राथमिक उद्देश्य पानी को डाइवर्ट कर 90 मेगावाट के रन-ऑफ-द-रिवर तिलोथ पावर प्लांट को पानी उपलब्ध कराना है।
- गौरतलब है कि भागीरथी नदी गंगा की दो शीर्ष धाराओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होती है।
- यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में प्रवाहित होती है।
- राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार भागीरथी नदी पर 1,743 मेगावाट की क्षमता वाली 16 जलविद्युत परियोजनाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं। टिहरी परियोजना इस पर अवस्थित महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना (HEP) है।

हेलंग-मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत बदरीनाथ हाईवे पर प्रस्तावित हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसका निर्माण कार्य जुलाई में शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस बाईपास मार्ग के निर्माण से बदरीनाथ धाम की दूरी 30 किमी. कम हो जाएगी। साथ ही चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी।
- ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत जोशीमठ से 13 किमी. पहले हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। जोशीमठ नगर के निचले हिस्से में करीब 5 किमी. तक इस मार्ग का निर्माण होगा।
- गौरतलब है कि 'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' ने मार्ग के विरोध में करीब एक वर्ष तक आंदोलन किया, जिस कारण निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।
- चीन सीमा क्षेत्र तक सेना की आवाजाही को सुगम बनाने का हवाला देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बाईपास मार्ग के निर्माण को ज़रूरी बताया, जिसके बाद मार्ग निर्माण को न्यायालय से हरी झंडी मिल गई है।
- बाईपास मार्ग के निर्माण से बदरीनाथ धाम की दूरी 30 किमी. कम हो जाएगी। अभी तक तीर्थयात्री हेलंग से जोशीमठ होते हुए मारवाड़ी पहुँचते रहे हैं, इसकी दूरी 20 किमी. है, जबकि प्रस्तावित बाईपास हेलंग-मारवाड़ी मार्ग करीब 5 किमी. का है।

उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के सम्मेलन में बताया कि राज्य में इस वर्ष 1 जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम इसी शिक्षा नीति के तहत तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने जा रही है।

नोट :

- गौरतलब है कि के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2020 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति में व्याप्त कमियों को दूर कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कायांतरण करना है।
- इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) को 100% करना।
- केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% सार्वजनिक व्यय करना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करना।

ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा के जलस्तर में एकाएक वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के जलागम क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलने से नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया, जिससे ज़िले में एक नई आपदा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर लोगों को घाटों से हटाने के साथ ही एसडीआरएफ की टीम घाटों पर तैनात की गई है।
- गौरतलब है कि गत वर्ष फरवरी में उत्तराखंड के चमोली ज़िले के तपोवन-रैनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड (Flash Flood) की घटना देखी गई थी, जिससे ऋषिगंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान पहुँचा था।
- अलकनंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के लिये सतोपंथ तथा अलकापुरी बांक में ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना उत्तरदाई है।
- अलकनंदा गंगा की दो मुख्य धाराओं में से एक है। दरअसल अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती हैं।
- अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर आदि शामिल हैं।

हिमालयन बर्ड सर्वे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी की गई बर्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन बर्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की 171 प्रजातियाँ देखी गई हैं।
- हिमालयी पक्षियों की यह गणना बर्ड काउंट इंडिया द्वारा विभिन्न हिमालयी राज्यों में ई-बर्ड वैश्विक पटल के तहत की गई है।
- गणना के दौरान उत्तराखंड में दुर्लभ रेडक्रॉस बिल के साथ ही मोनाल, द वाल क्रीपर, स्पाटेड नटक्रेकर और स्ट्रीक ब्रेस्टेड शिमिटर बैबलर समेत कई अन्य पक्षी देखे गए हैं।
- रिपोर्ट में विभिन्न हिमालयी राज्य/कें.शा.प्र./ज़िले एवं उनमें पक्षियों की प्रजातियों की संख्या निम्नलिखित है-

स्थान	पक्षी प्रजाति
उत्तराखंड	171
लद्दाख	148
हिमाचल प्रदेश	125

नोट :

जम्मू और कश्मीर	122
दार्जिलिंग	49
अरुणाचल प्रदेश	47
सिक्किम	36
कलिपोंग (पं. बंगाल)	08

'अपात्र को ना-पात्र को हाँ'अभियान

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2022 को उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा कर बताया कि खाद्य विभाग की 'अपात्र को ना-पात्र का हाँ'अभियान के तहत अब तक 3167 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से फर्ज़ी एवं अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान के तहत सबसे अधिक 1190 राशन कार्ड ऊधमसिंह नगर ज़िले से तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग ज़िले से राशन कार्ड सरेंडर किये गए है।
- खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसए) के अंतर्गत जिस गाँव से जितने अपात्र हटेंगे, उतनी ही संख्या में वहाँ पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे।
- उन्होंने प्रत्येक राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नाम की लिस्ट लगाने के साथ ही वहाँ सभी योजनाओं के मानक, हेल्पलाइन नंबर-1967 लिखने के निर्देश दिये हैं।
- अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिये वे लोग पात्र नहीं हैं जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपए से अधिक है। ये लोग 31 मई तक स्वयं अपने कार्ड सरेंडर करा सकते हैं।
- इसके बाद 1 जून से विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिसमें अपात्र पाए जाने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करा उससे रिकवरी की जाएगी।

शिव सर्किट में शामिल होगी 'महादेव गुफा'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कुमाऊँ मंडल विकास निगम के साहसिक पर्यटन प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने बताया कि चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के गाँव सीपू के निकट स्थित पौराणिक महादेव गुफा को शिव सर्किट से जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गुरुरानी के अनुसार कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा धारचुला की उच्च हिमालयी दारमा घाटी के अंतिम गाँव सीपू के समीप स्थित इस गुफा को आदि कैलाश यात्रा मार्ग में शामिल करने से धार्मिक पर्यटन को नया अवसर प्राप्त होगा।
- पौराणिक मान्यताओं (शिव पुराण) के अनुसार, सती के अग्निकुंड में समाहित हो जाने के बाद भगवान शिव ने इसी गुफा को अपनी तपस्थली बनाया था।
- गौरतलब है कि राज्य में विद्यमान विभिन्न शिव मंदिरों को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा शिव सर्किट प्रारंभ किया गया है।
- यह सर्किट उत्तराखंड के 24 शिव मंदिरों को शामिल करते हुए पौड़ी गढ़वाल स्थित एकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर बागेश्वर स्थित दांडेश्वर मंदिर में समाप्त होता है।

नोट :

म्युनिसिपल (Muni) बांड जारी करने की दिशा में उत्तराखंड का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में डॉ. उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रदेश के आठ नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग कराई जाएगी जिसके आधार पर ये नगर निगम शहरों के विकास के लिये बांड जारी कर फंड जुटा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- जिन नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग करवाई जाएगी उनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार शामिल हैं।
- उत्तराखंड में लगातार नगर निकायों में कम आय और ज़्यादा खर्च की वजह से निरंतर सरकार पर निर्भरता बनी रहने से विकास कार्य प्रभावित होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व अन्य खर्चों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग करवाना सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- स्थानीय निकायों पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी शहर के शासन ढाँचे और उनके वित्तीय सशक्तीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
- नगरपालिका (मुनि) बांड एक राज्य, नगरपालिका या काउंटी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिये जारी किया गया एक ऋण प्रतिभूति है, जिसमें राजमार्गों, पुलों या स्कूलों आदि का निर्माण किया जाना शामिल है।
- म्युनिसिपल बांडों की नियामक स्थिति को स्पष्ट करने और उन्हें निवेशकों के लिये सुरक्षित बनाने हेतु मार्च 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युनिसिपल बांडों को जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- उल्लेखनीय है कि बैंगलोर नगर निगम वर्ष 1997 में भारत में नगरपालिका बांड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय है।

उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 31 नए हेलीपैड

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि प्रदेश में सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हेली सेवाओं को विस्तार देने के लिये 31 स्थानों पर नए हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- ये हेलीपैड देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ज़िलों में बनाए जाएंगे। हेलीपैड बनाने का खर्च प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी।
- राज्य पर्यटन विभाग ने ज़िलाधिकारियों को अपने ज़िलों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के निकट हेलीपैड के लिये ज़मीन चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं, जिससे जल्द-से-जल्द इन ज़मीनों का अधिग्रहण कर यहाँ हेलीपैड तैयार कर हेली सेवाओं का संचालन किया जा सके।
- प्रदेश में उड़ान योजना के तहत देहरादून से चिन्यालीसौड़, देहरादून से गौंचर, देहरादून से टिहरी, देहरादून से श्रीनगर, देहरादून से अल्मोड़ा व हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिये हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।
- तीर्थाटन को देहरादून से केदारनाथ व चमोली ज़िले के विभिन्न स्थानों से केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिये हेली सेवाएँ संचालित की जा रही हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 51 स्थानों पर हेलीपैड बने हुए हैं।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड में नैसर्गिक सुंदरता से भरी पड़ी है। कहीं ऊँचे-ऊँचे पर्वत तो कहीं मखमली बुग्याल पर्यटकों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं। यहाँ सुदूरवर्ती पर्वतों के बीच बनी प्राकृतिक झीलें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होने के साथ ही पौराणिक महत्त्व की भी हैं।
- सरकार का प्रयास ऐसे पर्यटन स्थलों के आस-पास हेलीपैड तैयार करने का है, ताकि पर्यटक हेली सेवाओं के ज़रिये इन स्थानों तक पहुँच सकें और उन्हें कम-से-कम पैदल चलना पड़े। इसके साथ ही वे आकाश से भी बर्फ से लदी पहाड़ियों का सौंदर्य देख पाएंगे।
- प्रदेश सरकार की योजना निजी हेली कंपनियों के माध्यम से इन स्थानों पर हेली सेवाएँ शुरू करने की है। इससे न केवल सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि पर्यटकों को भी इससे सहूलियत मिल सकेगी।
- उत्तराखंड आपदा के लिहाज़ से भी संवेदनशील राज्य है। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। नए स्थानों पर बने हेलीपैड आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिये भी महत्त्वपूर्ण साबित होंगे।

नोट :